राज्य में 1292 करोड़ से मैदानी जिलों में बढ़ेगी बागबानी, शिवा परियोजना के मुख्य प्रोजेक्ट पर आठ जून को एडीबी के साथ एमओयू साइन करेगी सरकार

बागबानी के बड़े प्रोजेक्ट पर करार जल्द

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

एचपी शिवा परियोजना (हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागबानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना) की मुख्य परियोजना के लिए आठ जून को एशियन विकास बैंक, भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के मध्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपए होगी, जिसमें एशियन विकास बैंक द्वारा 1030 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 262 करोड़ रुपए वहन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से सात जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना के 28 विकास खंडों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 400 बागबानी क्लस्टरों के 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में चिन्हित किए 257 क्लस्टरों के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की निजी भूमि पर 'एक फसल-एक क्लस्टर' अवधारणा के तहत संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम व जापानी फल आदि अन्य उपोष्णकटिबंधीय फलों का रोपण किया जाएगा। शेष 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 143 क्लस्टरों, जिनका चिन्हीकरण किया जाना शेष है।

- बिलासपुर-हमीरपुर-कांगड़ा-मंडी-सोलन-सिरमौर -ऊना में किसानों की तकदीर बदलेगा शिवा
- एशियन विकास बैंक 1030 करोड़, सरकार 262 करोड़ खर्चेगी

15000 होंगे लाभान्वित

शिवा परियोजना से 15000 किसान-बागबान परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौध रोपण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 'बीज से बाजार' तक की संकल्पना पर आधारित इस परियोजना में जोड़ा जाएगा।

फल राज्य बनाने पर जोर

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को 'फल राज्य' बनाने के स्वपन को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के तहत क्लस्टरों के चयन के लिए मानदंड विकसित करते हुए सहभागी विधि से किया है। इससे प्रदेश में बागबानी को बढ़ावा मिलेगा।

14 फल-फसलें शामिल

विपणन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिन्हित 14 फल व फसलों की बाजार मांग के साथ ही इनकी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का भी अध्ययन किया है। एचपी शिवा परियोजना के पायलट चरण का पूर्व में ही सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा चुका है।

सरकार : सुक्खू

एच.पी. शिवा परियोजना के लिए 8 को होंगे समझौते पर हस्ताक्षर

शिमला (भूपिन्द्र) : एच.पी. शिवा परियोजना (हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्द्धन परियोजना) की मुख्य परियोजना के लिए आगामी 8 जून को एशियन विकास बैंक, भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के मध्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीज से बाजार तक की संकल्पना पर आधारित इस परियोजना में किसानों को वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कृषि के साथ-साथ फसलोपरांत मूल्य वर्धन करते हुए बाजार से जोड़ा जाएगा।

एचपी शिवा परियोजना के लिए आठ जून को होंगे समझौते पर हस्ताक्षर

राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में कहा कि एचपी शिवा परियोजना (हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना) की मुख्य परियोजना के लिए आठ जून को एशियन विकास बैंक, भारत सरकार व हिमाचल सरकार के मध्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपये होगी, जिसमें एशियन विकास बैंक (एडीबी) द्वारा 1030 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 262 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी। परियोजना को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न स्तरों पर सफलतापूर्वक उठाया गया। परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले निचले क्षेत्रों के सात जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना के 28 विकास खंडों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 400 बागवानी क्लस्टरों के 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में चिह्नित 257 क्लस्टरों के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की निजी भूमि पर 'एक फसल-एक क्लस्टर' अवधारणा के तहत संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम व जापानी फल आदि अन्य उपोष्णकटिबंधीय फलों का रोपण किया जाएगा। शेष 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 143 क्लस्टरों, जिनका चिन्हीकरण किया जाना शेष है, का विकास परियोजना के दूसरे चरण में किया जाएगा। इस परियोजना से 15000 किसान-बागवान परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौध रोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

एचपी शिवा परियोजना के पायलट चरण का पूर्व में ही सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा चुका है, जिसमें 17 क्लस्टरों के अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फल-पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें से 12 पायलट क्लस्टरों के किसानों ने संतरा, अमरूद व अनार का उत्पादन कर आर्थिक लाभ लेना शुरू कर दिया है।

शिवा परियोजना पर एशियन विकास बैंक 1030 और राज्य सरकार 262 करोड़ करेगी खर्च

शिमला। शिवा परियोजना (हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना) की मुख्य परियोजना के लिए आगामी 8 जून को समझौता हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि एशियन विकास बैंक, भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपये होगी। इसमें एशियन विकास बैंक की ओर से 1030 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 262 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे।

शिवा परियोजना के लिए 8 जून को होंगे समझौता हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी। परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न स्तरों पर सफलतापूर्वक उठाया गया। परियोजना के लागू होने से राज्य के किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा राज्य की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण व संतुलन की दिशा में भी राज्य का योगदान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले निचले क्षेत्रों के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना के 28 विकास खंडों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 400 बागवानी क्लस्टरों के 6,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 2 चरणों में किया जाएगा।

पहले चरण में चिह्नित किए गए 257 क्लस्टरों के तहत 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की निजी भूमि पर 'एक फसल-एक क्लस्टर' अवधारणा के तहत संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, पिकननट, जापानी फल आदि अन्य उपोष्ण कटिबंधीय फलों का रोपण किया जाएगा। दूसरे चरण में शेष 2,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 143 क्लस्टरों, जिनका चिह्नीकरण किया जाएगा। इस परियोजना से 15,000 किसान-बागवान परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौधरोपण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 'बीज से बाजार' तक की संकल्पना पर आधारित इस परियोजना में किसानों को वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक कृषि के साथ-साथ फसलोपरांत मूल्यवर्धन करते हुए बाजार से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो